भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-228

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत पहल

***228. श्री सनातन पांडेय:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस नीति के कार्यान्वयन के बाद से उक्त प्रयोजनार्थ नियत की गई बजटीय आवंटन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या देश में छात्रों द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण किए जाने के बाद उनके लिए लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित करने हेतु माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को कौशल आधारित/व्यवसायोन्मुखी बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत पहल के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सनातन पांडेय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद, इसके कार्यान्वयन के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी पहल की गई हैं।

स्कूल शिक्षा में कई पहलें की गई हैं जैसे स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश तीन-महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-आयामी पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत पीएम ई-विद्या करने के लिए 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार की गई खेल-आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री के लिए मूलभूत चरण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ; निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर); 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या उल्लास योजना आदि का कार्यान्वयन।

उच्चतर शिक्षा में, राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचा (एनएचईक्यूएफ) जैसे दिशा-निर्देशों/विनियमों के संयोजन में अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट ढांचा; उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में बहुआयामी प्रवेश और निगम; उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम जारी रखना; व्यक्तिगत छात्र की स्वचलित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो प्री-प्राइमरी से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना; ओडीएल / ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; बेहतर शिक्षण के लिए संकाय में दक्षताओं को बढ़ाने के लिए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पुनः परिकल्पना की गई; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल को बढ़ाने

और फिर से कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; एचईआई को उद्योग के विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के संबंध में दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशों से छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों हेतु दिशानिर्देश; युगल, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग; विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए विनियम; अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को सन्निहित करना।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में छात्राओं के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण /पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और संभारतंत्र गलियारों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और हर जिले में 1 बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में एनईपी 2020 के अनुरूप स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ-एसई) शैक्षणिक विषयों के साथ समानता सुनिश्चित करने हेतु कौशल शिक्षा को सीधे मध्य और माध्यमिक चरणों में इसे एकीकृत करके संस्थागत बनाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड 6 से 8 के छात्रों के लिए कौशल प्रदर्शन और ग्रेड 9 से 12 के लिए एनएसक्यूएफ-अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करके व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। माध्यमिक स्तर पर, छात्र कौशल मॉड्यूल को एक अतिरिक्त विषय के रूप में चुनते हैं जबकि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, कौशल पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषयों के रूप में कार्य करते हैं। कुल 138 स्वीकृत रोजगार भूमिकाएं प्रदान की जाती है और प्रत्येक में संप्रेषण, स्व-प्रबंधन, आईसीटी, उद्यमिता और हरित कौशल को कवर करने वाला एक नियोजनीयता कौशल मॉड्यूल शामिल है। विभाग स्कूलों में पीएमकेवीवाई 4.0 को भी लागू कर रहा है, जिसमें 350 केंद्रीय विद्यालय कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। 21,700 से अधिक स्कूलों में अब नवाचार, उद्यमिता, विवेचनात्मक सोच और आईपी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नवाचार परिषद हैं।

माध्यमिक स्तर (ग्रेड 9 से 12) पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नियोजनीयता कौशल के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं, जो सभी कौशल पाठ्यक्रमों में अंतर्निहित हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

द्वारा विकसित कौशल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की भूमिकाओं पर आधारित हैं, जो एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है।

पाठ्यक्रम में नियोजनीयता कौशल मॉड्यूल को रोजगार की भूमिकाओं/स्वयम पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है जिसमें संप्रेषण कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

एनसीईआरटी ने कौशल शिक्षा तक पहुंच, विशेष रूप से जहां भौतिक संसाधन सीमित हैं, का विस्तार करने के लिए ई-लर्निंग सामग्री, वीडियो और आभासी कौशल प्रयोगशाला (वीएसएल) विकसित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी छात्र अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक, नौकरी के लिए तैयार कौशल विकसित कर सकें।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) युवा पीढ़ी के कौशल और दक्षता के स्तर को बढ़ाने और उपलब्ध विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाने के लिए कक्षा 9-10 में 22 और कक्षा 11-12 में 43 कौशल विषय प्रदान करता है।

नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित), रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और 3डी प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं।

आईआईटी मद्रास के सहयोग से शुरू किया गया स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम), प्रमुख संस्थानों द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रस्तुत करता है और "कोई भी, कहीं भी, कभी भी" सीखने के दृष्टिकोण के साथ निःशुल्क उपलब्ध है। 5.64 करोड़ से अधिक के संचयी नामांकन के साथ 4400 से अधिक विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। कौशल विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए, स्वयम प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में, 16 क्षेत्रों में 480 से अधिक पाठ्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

"मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि में 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कृत्रिम मेधा (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को मंजूरी दी थी। शिक्षा मंत्रालय ने तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना के लिए तीन शैक्षणिक संस्थानों को मंजूरी दी - आईआईएससी बेंगलुरु में स्वास्थ्य में एआई का सीओई, आईआईटी रोपड़ में कृषि में एआई का सीओई और आईआईटी कानपुर में टिकाऊ शहरों में एआई का सीओई। इसके अलावा, बजट 2025-26 में 500.0 करोड़ रुपये के कुल

परिव्यय के लिए शिक्षा में एक नए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की घोषणा की गई है, जिसका निर्देशन आईआईटी मद्रास द्वारा किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने और युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भी लागू करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कौशल विकास को तकनीकी शिक्षा में शामिल करके सक्रिय रूप से सुदृढ़ बना रहा है। यह नियमित पाठ्यक्रम के साथ जुड़े ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी करता है जिसमें कौशल-केंद्रित कार्यक्रमों, अनिवार्य इंटर्नशिप, और व्यावसायिक डिग्री जैसे बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वीओसी) शामिल है। इन पहलों को छात्रों की व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करने और नियोजनीयता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एआईसीटीई-अनुमोदित संस्थानों के स्व-रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर, डिप्लोमा प्लेसमेंट वर्ष 2023-24 में 1,80,866 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,91,801 हो गया। इसी अवधि के दौरान अवर स्नातक प्लेसमेंट में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 4,10,843 से बढ़कर 4,71,227 हो गई। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक अनुभव सहित इंटर्नशिप, कौशल-वृद्धि और संकाय के कौशल संवर्धन के सहयोग प्रदान करने के लिए प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, इसने वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट आवंटन 93,224.31 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 1,04,277.72 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 के लिए 1,12,899.47 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 के लिए 1,21,117.77 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 के लिए 1,28,650.05 करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 के लिए 1,39,289.48 करोड़ रुपये किया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 83562.26 करोड़ रुपये का बजट आवंटन विभाग के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। बजट अनुमान (बीई) 2025-26 की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में डीओएसईएल के लिए बजट आवंटन में 4,990 करोड़ रुपये (6.35%) की समग्र वृद्धि हुई है।

उच्च शिक्षा के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समग्र बजट आवंटन 55,727.22 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में उच्चतर शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में ₹5,649.27 करोड़ (11.28%) की समग्र वृद्धि हुई है।

*****